3 वत्स, राम रतन शर्मा व दीप्ति वत्स को सम्मन जारी

5 साधारण किसान परिवार से सत्ता के शिखर तक

6 आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 40 प्रति सोमवार, 9 फरवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

आस्था-संस्कृति-परंपरा का अनुपम संगम; छत्तीसगढ़ की सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजिम कुंभ कल्प 2026 परंपरा और विकास का सुंदर समन्वय प्रस्तुत कर रहा है। सुशासन की मजबूत नींव पर खड़ा यह आयोजन आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई दिशा दे रहा है। राजिम कुंभ कल्प 2026 इसी सांस्कृतिक उत्थान का सशक्त उदाहरण है, जहाँ परंपरा और प्रगति एक साथ आगे बढ़ रही हैं।

राजिम कुंभ कल्प 2026 छत्तीसगढ़ की सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है, जहां लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित 'छत्तीसगढ़ के प्रयाग' राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर 01 से 15 फरवरी 2026 (माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि) तक भव्य रूप से किया जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहाँ देश भर के साधु-संत और लाखों श्रद्धालु संगम स्नान व राजीव लोचन के दर्शन करने पहुँचते हैं। यह आयोजन भगवान राजीव लोचन के दर्शन और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि व समृद्धि पाने का एक बड़ा धार्मिक उत्सव है। (शेष पेज 7 पर)

4.21 लाख करोड़ के बजट वाला मप्र 4.65 लाख करोड़ के कर्ज में

बड़ा सवाल: कमलनाथ सरकार में पटरी पर थी अर्थव्यवस्था, मोहन सरकार में क्यों बिगड़े हालात?

-विजया पाठक

कर्ज में गले तक डूबी मोहन सरकार में मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार से डबल मुसीबत में फँस गई है। एक तरफ़ प्रदेश के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है तो दूसरी तरफ़ केंद्र सरकार राज्य को उसके हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। हक़ीक़त यह है कि मध्य प्रदेश के 25 विभागों के लिए केंद्र सरकार ने 01 अप्रैल 2025 से 20 जनवरी 2026 के बीच में एक रुपया नहीं दिया है। (शेष पेज 2 पर)

दांगी IPS अफसरों के प्रमोशन से छत्तीसगढ़ में मचा सियासी बवाल

भूपेश बघेल के राज में कई आईपीएस अफसरों ने किया जमकर भ्रष्टाचार

-विजया पाठक

हाल ही में छत्तीसगढ़ के 16 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। सूची में अलग-अलग बैच के कई अफसरों के नाम हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। इनमें एक अफसर को एडीजी, दो को आईजी और 08 अफसरों को डीआईजी के पद पर पदोन्नति मिली है। राज्य कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर डॉ. आनंद छाबड़ा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। साल 2008 के दो आईपीएस अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रशांत कुमार अग्रवाल और मिलना कुर्रे शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 2008 बैच की आईपीएस अफसर नीथू कमल को पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। इसी तरह डी. श्रवण को भी समान तिथि से आईजी वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति मिली है। डॉ. आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल और अभिषेक पल्लव तीनों IPS अफसरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 06/2024 महादेव सट्टा ऐप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 17(क) के अंतर्गत विवेचना स्तर पर लंबित हैं। रजनेश सिंह के विरूद्ध ईओडब्ल्यू रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 06/2019 व 07/2019 (फोन टैपिंग प्रकरण) में माननीय न्यायालय में दिनांक 04/07/2024 को अंतिम रिपोर्ट पेश किया गया है, जो न्यायालय में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में भी रजनेश सिंह (भापुसे) को समस्त प्रयोजन हेतु परिणामी लाभ दिया गया है। फिर भी चारों अफसरों को पदोन्नति दी गई। कुछ जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कथित "दागी" या विवादित (जैसे महादेव ऐप मामले) अफसरों को प्रमोशन मिलने का मुख्य अर्थ यह है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर लगे आरोप या तो सिद्ध नहीं हुए या वे आरोप मुक्त हो चुके हैं। (शेष पेज 2 पर)

क्या संकेत देता है मुख्यमंत्री का पत्रकारों के सवालों से डरना?

सवालों से डरती सत्ता या सवालों से मज़बूत होता लोकतंत्र

-विजया पाठक

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को अक्सर चौथे स्तम्भ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह केवल खबरों का स्रोत नहीं है, बल्कि यह सरकार और शासन की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मीडिया स्वतंत्र हो और निष्पक्षता के साथ सच्चाई को उजागर करने का अधिकार रखता हो। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि मीडिया के प्रति व्यवहार और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के तरीके, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। (शेष पेज 6 पर)

कमलनाथ सरकार में पटरी पर थी अर्थव्यवस्था, मोहन सरकार में क्यों बिगड़े हालात?

(पेज 1 का शेष)

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के किसान कल्याण, कृषि विकास और ग्रामीण विकास विभाग से ही 7774.54 करोड़ रुपए नहीं मिल सके हैं। केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 44,355.83 करोड़ रुपए मिलने थे। अब तक 10 माह बीतने पर भी सिर्फ 9753.05 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं। इस तरह सिर्फ 22 फीसदी फंड ही दिल्ली से आया है। पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन के लिए 8561.22 करोड़ दिए जाने हैं लेकिन दस माह में एक रुपए भी नहीं दिए गए। मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम के लिए 150 करोड़ और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है लेकिन एक रुपए भी नहीं दिए गए। दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश सरकार केंद्र से अपने हिस्से का पैसा प्राप्त नहीं कर पा रही है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है और प्रदेश के भाजपा नेता प्रदेश की जनता के हित को पार्टी हित के सामने गिरवी रख रहे हैं। यही स्थिति बनी रही तो पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रहा मध्य प्रदेश भारी आर्थिक संकट में फैस जाएगा। सोचने वाली बात है कि आखिरकार मोहन सरकार अपनी ही केन्द्रीय सरकार से अपने हिस्से का पैसा निकलवाने में असमर्थ क्यों है।

कमलनाथ सरकार ने नहीं बिगड़ने दी अर्थव्यवस्था

प्रदेश में भले ही कमलनाथ सरकार ने केवल 15 महीने शासन किया लेकिन सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया। वित्तीय दायरे में ही रहकर प्रदेश को आगे चलाया। जबकि उसी समय प्रदेश के लाखों किसानों का कर्जा भी माफ किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दूरगामी सोच और नीतिगत फैसले लेकर राज्य की गति प्रदान की। लेकिन वर्तमान सरकार के पास ऐसा कोई विजन नहीं है।

बजट से ज्यादा हो गया मध्यप्रदेश का कर्जा

वर्तमान समय में मध्यप्रदेश इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो गये हैं कि सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। 4.21 लाख करोड़ के बजट वाला मध्य प्रदेश 4.65 लाख करोड़ के कर्ज में चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार कर्ज लेकर ठेका देने और कमीशन बटोरने में लगी रहती है

केन्द्र सरकार ने रोके लगभग 35 हजार करोड़ रूपये

और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। यह गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों की देन है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को और ज्यादा कर्ज के बोझ में दबाने की बजाय प्रदेश पर मौजूदा कर्ज को चुकाने और कर्ज मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें।

मुफ्त की रेवड़ी बांटने में बढ़ रहा कर्जा

प्रदेश में मोहन सरकार की वर्तमान स्थिति तो यह बता रही है कि सरकार की आमदनी अठन्नी है और खर्चा रूपैया है। बावजूद इसके मोहन सरकार मुफ्त की रेवड़िया बांटने में कसर नहीं छोड़ रही है। खासकर लाड़ली बहना योजना की किस्त डालने के लिए हर माह कर्ज लेती है। हालात इतने बदतर हो गये हैं। सोचन वाली बात है कि जब सरकार की स्थिति खराब है तो ऐसी योजनाओं को चलाने का क्या मतलब है। तत्कालीन वाहवाही लूटने के चक्कर में सरकार प्रदेश को गर्त में ले जा रही है। आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक लगभग 30 हजार का कर्जदार है। उसके बाद भी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय फिजूलखर्ची कर रही है। हालात ये है कि सरकार अपनी ब्रांडिंग करने के लिए करोड़ों रूपये फूंकने में एक बार भी नहीं सोचती है। पिछले दो साल में ही सरकार ने इंवेस्टर्स मीट के नाम पर अरबों रूपये खर्च किये हैं। विभिन्न शहरों में आयोजित आयोजनों में केन्द्रीय नेतृत्व को खुश करने के चक्कर में मोहन सरकार ने पैसों को पानी की तरह बहाया है। जिसका नतीजा आज तक जमीन पर नहीं दिखा है। इसके अलावा शासकीय आयोजनों की भव्यता, दिव्यता पर खर्च अलग से है। आखिर बीजेपी सरकार का यह कौनसा कल्चर है।

गलत नीतियों के चलते कर्ज के दलदल में मोहन सरकार

प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने का मध्यप्रदेश सरकार का कोई रोडमेप नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार के पास न कोई नीति है और न ही नियत है। यदि सरकार के पास सही और सटीक नीतियां होती तो आज प्रदेश की यह स्थिति नहीं होती। नीतियां भी ऐसी बनाई जा रही है जो सिर्फ दिखावा भर हों। क्या दिखावे से प्रदेश का विकास होता है। विकास का दिखावा है और आर्थिक तरक्की की जुमलेबाजी हैं। न किसानों पर, न नौजवान बेरोजगारों पर और न ही गरीबों के कल्याण पर फोकस है। पूरा सिस्टम कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है। सरकार के प्रशासनिक मुखिया तक को कहना पड़ रहा है कि कलेक्टर बगैर कमीशन के काम नहीं करते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।

दांगी IPS अफसरों के प्रमोशन से छत्तीसगढ़ में मचा सियासी बवाल

(पेज 1 का शेष)

यह राज्य सरकार की रूटीन कैडर प्रबंधन प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पुलिस व प्रशासनिक कमांड स्ट्रक्चर को मजबूत करना और कार्यकुशलता बनाए रखना है। जिन अधिकारियों पर पिछली सरकार के समय मामले दर्ज हुए थे, उन्हें पदोन्नति देकर यह संदेश दिया गया है कि तकनीकी रूप से उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने पुलिस महकमे पर छापा मारा था। सट्टेबाजों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर माह लाखों रुपये लेने वाले चार आईपीएस, दो एडिशनल एसपी, दो इंस्पेक्टर समेत दो हवलदारों का नाम सामने आया था। राज्य वित्त आयोग के पूर्व सदस्य और अधिवक्ता नरेशचंद्र गुप्ता ने महादेव ऑनलाइन सट्टे को लेकर 18 फरवरी, 2025 को सीबीआई के डायरेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें पुलिस अफसरों की संलिप्तता का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। महादेव एप के प्रमोटर शुभम सोनी ने वर्ष 2023 में वीडियो जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संरक्षण राशि के रूप में 508 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया था।

एप के प्रमोटरों के संपर्क में थे आईपीएस

एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी की हिरासत में कबूल किया था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई से उसने 81 करोड़ से अधिक प्राप्त किए थे। इस रकम को आईपीएस समेत पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को वितरित किया। मई 2022 से पहले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सीधे तौर पर आईपीएस आनंद छाबड़ा, दुर्ग के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव, रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ और प्रशांत अग्रवाल के संपर्क में थे। दरअसल, उस समय उनके पास छोटे स्तर का व्यवसाय था और उन्हें उनसे सुरक्षा मिली हुई थी। जैसे-जैसे इनका क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ में फैलता गया, पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी की भागीदारी जरूरी हो गई। इसके बाद सभी अफसरों ने पद का दुरुपयोग करके उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया और बदले में उन्होंने उनसे लाखों की रिश्वत ली।

एसपी ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, मचा सियासी बवाल

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उनके पत्र में पुलिस महकमे में पदोन्नति को लेकर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र सामने आने के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह छवई ने सीएम को पत्र लिखकर अपने साथ हुए अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की पीड़ा व्यक्त की है। धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर प्रमोशन नहीं दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह छवई वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई पदोन्नति सूचियों 10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025 में उनके नाम पर विचार किया गया, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए, छवई ने गृह मंत्रालय के 15 जनवरी, 1999 के दिशानिर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पदोन्नति को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि कोई अधिकारी निलंबित न हो, उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर न किया गया हो, या वह किसी आपराधिक मुकदमे का सामना न कर रहा हो। अधिकारी ने चयनात्मक न्याय का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जहां एक मामूली जांच के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई है, वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों सहित अधिक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अन्य अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है। पत्र में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के अधिकार का जिक्र करते हुए कहा गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मुद्दे ने पदोन्नति नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटनाक्रम ने पुलिस सेवाओं के भीतर पदोन्नति नीतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से सतर्कता निगरानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन पर। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह मामला सिविल सेवकों के करियर में प्रगति के निर्णयों में लंबित जांचों के उपयोग पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। पत्र में चारों अफसरों जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, का जिक्र किया और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 15 जनवरी 1999 के पदोन्नति नियमों की कंडिका-11 का हवाला दिया। इसके अनुसार निलंबन के दौरान, आरोप पत्र जारी होने पर और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित होने की स्थिति में पदोन्नति रोकी जा सकती है। धर्मेंद्र छवई का कहना है कि उनके मामले में ये शर्तें लागू नहीं होतीं, फिर भी उन्हें न तो वरिष्ठ वेतनमान दिया गया और न ही उप पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि समान स्थिति वाले अन्य अधिकारियों को लाभ दिया गया। चिट्ठी में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का खुला उल्लंघन बताया गया है। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया गया और व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते पदोन्नति रोकी गई। अधिकारी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मांग की है कि नियमों के तहत विचार करते हुए उन्हें समतुल्य वेतनमान और पदोन्नति प्रदान की जाए, ताकि न्याय मिल सके और समानता का अधिकार सुरक्षित रह सके। यह चिट्ठी मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

08 अफसर डीआईजी बने

वर्ष 2012 के 08 आईपीएस अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणी, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल हैं।

05 अधिकारियों को चयन श्रेणी

2013 के चार IPS अधिकारियों को चयन श्रेणी में पदोन्नत किया गया है। इनमें डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल और यशपाल सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जितेंद्र शुक्ला (भापुसे-2013) को भी चयन श्रेणी में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।

सुर्खियों में रहा IAS-IPS अधिकारियों का काला चिट्ठा

इस बीच प्रदेश के कोल खनन परिवहन घोटाले में लिप्त रायपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर के तत्कालीन एसएसपी-कलेक्टर और अन्य अफसरों की संलिप्ता का काला चिट्ठा सुर्खियों में है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ कैडर के आल इंडिया सर्विस के कतिपय चुनिंदा अधिकारी भूपेश राज में आए दिन करोड़ों की रकम पर हाथ साफ़ कर रहे थे। उनके लेन-देन का नमूना मात्र देखकर आप रोजाना के अवैध कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं। घोटाले के किंगपिन से इन अफसरों का करीब का नाता बताया जाता है। ये IAS और IPS अधिकारी आपस में सांठगांठ कर छत्तीसगढ़ शासन की तिजोरी को किसी प्रोफेशनल गिरोह की तर्ज पर चूना लगा रहे थे। उनका लेनदेन गंभीर आर्थिक अपराध के दायरे में बताया जाता है। एक IAS अधिकारी ने कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी को 11 करोड़ 05 लाख की नगद रकम की अदायगी की थी, जबकि वर्दीधारी एक प्रभावशील ASP ने इसी कोल माफिया सूर्यकान्त तिवारी से 05 करोड़ 67 लाख की नगदी प्राप्त की थी। इसके अलावा ED ने अन्य IAS-IPS की कार्यप्रणाली से भी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा पत्र लिखकर महीने भर पहले अवगत कराया था। लेकिन अकार्यकुशल निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी ने ED के इस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

दिल्ली कोर्ट ने डॉ. पंकज वत्स, राम रतन शर्मा व दीप्ति वत्स को सम्मन जारी किया

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। एमएनसी में कार्यरत पीड़िता युवती ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में डॉ. पंकज वत्स एवं उनके पिता रामरतन शर्मा पर एफआईआर दर्ज करवाई है। शादी का झांसा देकर डॉ. वत्स ने पीडित युवती से संबंध बनाए। डॉ. पंकज वत्स पीड़ित युवती को हमेशा यह समझाने में कामयाब रहा कि मेरी पत्नी दीप्ति वत्स से कोई

पति-पत्नी का संबंध नहीं है। मेरी पत्नी मुझे अनादर करती रहती है। इसलिए मैं उसको तलाक देकर तुम्हे पत्नी बनाऊंगा और तुम हमारे परिवार के जिंदगी व्यतित करोगी। डॉ. पंकज वत्स के पिता (राम रत्न) इस मामले मे अपने बेटे का पक्ष रखकर हमेशा उसे सपोर्ट करता रहा है। पीड़ित युवती ने कहा कि डॉ. वत्स व राम रत्न शर्मा ने मुझे और मेरे परिवार को काफी धमकाया। बाद में काफी विवाद बढने के बाद उन्होंने मुझे रेस्टोरेन्ट में मिलने को कहा और डॉ. पंकज वत्स व उनके पिता ने आश्वासन दिया कि पुरानी बातें भूलकर तुम दोनों मिलके एक नई खुशहाली जिंदगी जियो और मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ बनी रहेगी। लेकिन कुछ मिंटो के बाद दोनों बाप-बेटा का मिजाज बदल गया और कहा कि तुम एक एग्रीमेन्ट हम लोगों के साथ कर लो और मेरा बेटा से कोई संबंध रहा ही नहीं है। लेकिन इस तरह के एग्रीमेंन्ट नही मानने के बाद वो दोनों पुत्र व पिता मुझे गालियां देकर निकाल गए।

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्ट-अप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को स्वीकृति

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद ने "छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30" को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक सशक्त, समावेशी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजन हो तथा सतत आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो। यह नीति राज्य के युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता की दिशा में प्रेरित एवं सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के माध्यम से वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, बाजार संपर्क, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा समर्थन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नीति में 100 करोड़ रूपए के छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड, 50 करोड़ रूपए के क्रेडिट रिस्क फंड, सीड फंड सहायता (10 लाख रूपए तक), ब्याज अनुदान, किराया अनुदान, पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, रोजगार सृजन सब्सिडी सहित कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों तथा पब्लिक वेलफेयर एवं सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन भी नीति का प्रमुख हिस्सा हैं।

युवक की मौत पर विरोध प्रदर्शनः परिजनों ने किया स्टेट हाईवे पर चक्काजाम, आरोपी पटवारी की गिरफ्तारी की मांग

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के गाडरवारा में एक सड़क हादसे में युवक रोहित भरेले की मौत हो गई। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी पटवारी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बुधवार रात गाडरवारा में हुई इस घटना में क्रेटा कार की टक्कर से रोहित भरेले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार को हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और स्टेट हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांत कराया गया और आवागमन बहाल हो सका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हादसा गाडरवारा थाने के ठीक सामने हुआ था, फिर भी आरोपी पर तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि आरोपी के पटवारी होने के कारण मामले में नरमी बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड परीक्षाओं के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा और प्रसारण बेतुकी हास्यास्पद बात : अजय खरे

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रीवा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने केन्द्र एवं राज्य स्तरीय उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा शुरू होने के कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम को विद्यार्थियों के परीक्षा अभ्यास में व्यवधान बताया है। खरे ने कहा कि यह परीक्षा पे चर्चा का समय नहीं बल्कि पुनः अभ्यास का है। देश भर में करोड़ों छात्र छात्राएं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का तमाम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित करके परीक्षार्थियों के तनाव को कम करने की बात अत्यंत गैर जिम्मेदाराना, बेतुकी, हास्यास्पद और कीमती समय की बर्बादी है। खरे ने कहा कि विद्यार्थियों के दाखिले के समय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाई करने के तरीके बताने पर चर्चा हो सकती है लेकिन जब परीक्षा सिर पर हो तो ऐसा करना कदापि उचित नहीं है। खरे ने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम और बस्ते के बोझ के अलावा फीस, किताब कॉपी, स्कूल की ड्रेस आदि के खर्च का तनाव बना रहता है। भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों की चिंता स्वाभाविक है। खरे ने कहा कि बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं होने से छात्रों छात्राओं में तनाव रहता है। अभाव के जीवन से किसी भी परिवार में तनाव स्वाभाविक है। यहां तो भूखे भजन ना होय गोपाला वाली कहावत चरितार्थ है। सरकार को इस दिशा में कारगर उपाय कर तनाव मुक्त जीवन की पहल करना चाहिए।

मध्यप्रदेश में महिला-बाल अपराध के बढ़ते आंकड़ों के बीच व्यवस्था की शर्मनाक विफलता

सागर के सरकारी हॉस्टल में 12 साल की छात्रा से दुष्कर्म

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. सागर। मध्यप्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम सरकारी दावों के बीच सागर जिले से सामने आया यह मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत भी उजागर करता है। जिस कस्तूरबा गांधी सरकारी हॉस्टल को गरीब और ग्रामीण परिवारों की बच्चियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, वहीं एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा चार महीने तक डर, धमकी और चुप्पी के बीच जीने को मजबूर रही। इस दर्दनाक सच से पर्दा तब उठा, जब पेट दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल जांच में छात्रा के तीन माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही सामने आई एक ऐसी कहानी, जिसने प्रशासन, समाज और सिस्टम—तीनों को कठघरे में खड़ा कर दिया।

गरीबी से शिक्षा तक का सफर, जो सुरक्षा पर आकर टूट गया

पीड़िता मूल रूप से विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। माता-पिता के पास इतने साधन नहीं थे कि वे बेटी की पढ़ाई गांव में ही जारी रख सकें। इसी उम्मीद में उसे सागर के सरकारी हॉस्टल में भेजा गया, ताकि वह आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर सके और भविष्य संवार सके। हॉस्टल में वह पिछले दो वर्षों से रह रही थी। माता-पिता को भरोसा था कि सरकारी व्यवस्था उनकी बेटी की सुरक्षा करेगी, लेकिन यही भरोसा सबसे बड़ी चूक बन गया।

चार महीने तक चला अपराध, खामोशी बनी हथियार

छात्रा के बयान के मुताबिक, अल्ताफ (35) नाम का युवक, जो हॉस्टल में सब्जी सप्लाई करता था, सितंबर 2025 में जबरन उसके कमरे में घुस आया। उसने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी-सहमी बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया। न नजदीकी स्टाफ को,न हॉस्टल प्रबंधन को,न अपने परिवार को।

धमकियों के बल पर आरोपी को जब भी मौका मिला, उसने अपराध दोहराया। यह सिलसिला करीब चार महीने तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।

मध्यप्रदेश में महिला-बाल अपराधः आंकड़े जो डराते हैं

सागर की यह घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि-

मध्यप्रदेश में हर साल 30 हजार से अधिक महिला अपराध दर्ज होते हैं।

बलात्कार के मामलों में राज्य लगातार देश के शीर्ष राज्यों में।

नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी।

अधिकतर मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित या भरोसेमंद व्यक्ति।

विशेषज्ञ मानते हैं कि हॉस्टल, आश्रय गृह और आवासीय संस्थानों में निगरानी की कमी अपराध की सबसे कमजोर कड़ी है।

सम्पादकीय

ट्रंप की ट्रेड पलटी और भारत के लिए अवसर की राजनीति

डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही वैश्विक राजनीति में अनिश्चितता, तीखे बयान और नीतिगत पलटवार की छवि उभर आती है। एक बार फिर उन्होंने वही किया, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। भारत के साथ व्यापार को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात करने वाले ट्रंप ने अब केवल 18 प्रतिशत ट्रेड शुल्क लगाने का निर्णय लेकर अपने ही पुराने तेवरों से अलग रास्ता चुना है। यह फैसला न केवल अमेरिका की रणनीतिक मजबूरियों को उजागर करता है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक हैसियत को भी रेखांकित करता है। ट्रंप का व्यापार दर्शन हमेशा "अमेरिका फर्स्ट" के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। पहले वे भारत को "टैरिफ किंग" कह चुके हैं और कई बार भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में 18 प्रतिशत का आंकड़ा एक नरम रुख माना जा रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत को अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आर्थिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।

इस पलटी के पीछे अमेरिका की आंतरिक आर्थिक चुनौतियाँ भी हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। आईटी, फार्मास्युटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी सेवाओं में भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बन चुका है। ऐसे में अत्यधिक शुल्क लगाना अमेरिका के अपने उपभोक्ताओं और उद्योगों को नुकसान पहुँचा सकता था। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह फैसला राहत भरा जरूर है, लेकिन पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। 18 प्रतिशत शुल्क भी भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बना रहेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से ही मुनाफा सीमित है। फिर भी, यह दर उन आशंकाओं से कहीं कम है, जिनमें 25 या 30 प्रतिशत तक के शुल्क की चर्चा थी।

यह घटनाक्रम भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश भी देता है कि भावनाओं से नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक मजबूती से ही वैश्विक दबावों का सामना किया जा सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण और निर्यात विविधीकरण पर जो जोर दिया है, उसी का परिणाम है कि आज कोई भी महाशक्ति उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। ट्रंप की यह पलटी यह भी दर्शाती है कि वैश्विक राजनीति में स्थायित्व अब अपवाद बन चुका है। नीतियाँ व्यक्ति-केन्द्रित होती जा रही हैं और फैसले तत्काल लाभ-हानि के गणित से तय हो रहे हैं। ऐसे में भारत को दीर्घकालिक दृष्टि रखते हुए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से बचना होगा और वैकल्पिक बाजारों की तलाश को और तेज करना होगा। कुल मिलाकर, ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए न तो पूर्ण जीत है, न ही हार। यह एक संकेत है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक व्यापार की अनिश्चित लहरों में उसे हर कदम सोच-समझकर रखना होगा।

सियासी गहमागहमी

मोदी सरकार का केन्द्रीय बजट मध्यमवर्गीय परिवार को मिली सिर्फ सहानुभूति

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें ठोस राहत से अधिक सहानुभूति के शब्द दिखाई दिए। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा मध्यम वर्ग इस बार भी प्रत्यक्ष कर राहत या खर्च घटाने वाले ठोस उपायों की प्रतीक्षा करता रह गया। बजट भाषण में मध्यम वर्ग के योगदान की सराहना जरूर की गई, लेकिन आयकर स्लैब, होम लोन ब्याज में अतिरिक्त छूट या शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर रियायत जैसे मुद्दों पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने दीर्घकालिक विकास, पूंजीगत निवेश और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, जो भविष्य के लिए आवश्यक है, परंतु वर्तमान में मध्यम वर्ग पर बढ़ते आर्थिक दबाव को यह बजट कम करता नहीं दिखा। बढ़ती महंगाई ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को पहले ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों के इलाज तक हर खर्च बोझ बनता जा रहा है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस समिति में बड़े बदलाव की अटकलों के कारण हलचल तेज

मध्यप्रदेश कांग्रेस समिति में बड़े बदलाव की अटकलों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लंबे समय से संगठनात्मक निष्क्रियता और चुनावी असफलताओं से जूझ रही कांग्रेस अब नेतृत्व और संरचना में परिवर्तन के संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि कई प्रमुख चेहरों की जिम्मेदारियाँ बदली जा सकती हैं या उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संगठन को फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय किया जाए। पुराने और आजमाए हुए चेहरों पर निर्भरता ने पार्टी को स्थिरता तो दी, लेकिन ऊर्जा और आक्रामकता की कमी भी उजागर की है। ऐसे में नए चेहरों को आगे लाने की मांग तेज हो रही है, जो कार्यकर्ताओं में विश्वास और जनता में उत्साह जगा सकें। हालांकि बदलाव आसान नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पुरानी समस्या रही है। किसी भी बड़े फेरबदल से असंतोष और अंदरूनी टकराव की आशंका बनी रहेगी। फिर भी पार्टी के लिए यह जोखिम उठाना अब मजबूरी बनता जा रहा है। कुल मिलाकर, यदि कांग्रेस वास्तव में सत्ता की वापसी का सपना देख रही है, तो संगठन में केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। उसे नेतृत्व, रणनीति और कार्यशैली तीनों स्तरों पर ठोस और साहसिक फैसले लेने होंगे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

बस सवालों से इतनी घबराहट?

मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे,
झूठ की शरण ले ली।

खैर, जो उचित समझा, वही किया।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

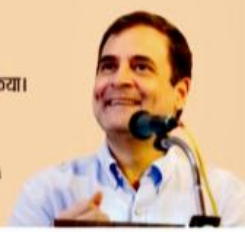

भारत की अण्डर-19 क्रिकेट टीम ने रिकार्ड 6वीं बार अण्डर-19 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है

वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ 175 की पारी की बदौलत, भारत ने 50 ओवर में 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।

जवाब में इंग्लैंड की पारी 311 रनों पर सिमट गई। -कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

साधारण किसान परिवार से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले नेता हैं कल्याण सिंह

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जो अपने संघर्ष, दृढ़ता और वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। कल्याण सिंह ऐसे ही एक नेता थे, जिन्होंने उत्तरप्रदेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले जननेता भी थे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ जिले के मढ़ौली गाँव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े कल्याण सिंह ने प्रारंभ से ही सामाजिक विषमताओं और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को निकट से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बने। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त की और गणित विषय में एमए करने के बाद अध्यापन कार्य से जुड़े। राजनीति में उनका प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के माध्यम से हुआ। संघ की विचारधारा ने उनके व्यक्तित्व को अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना से समृद्ध किया। बाद में वे जनसंघ से जुड़े और संगठनात्मक कार्यों के माध्यम से राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 1967 में वे पहली बार उत्तरप्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। कल्याण सिंह का राजनीतिक कद उस समय और ऊँचा हुआ जब वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। वर्ष 1991 में वे पहली बार उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह वह दौर था जब प्रदेश सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उनके कार्यकाल में प्रशासनिक सख्ती, कानून-व्यवस्था पर जोर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख देखने को मिला। उनका नाम भारतीय राजनीति में विशेष रूप से अयोध्या आंदोलन से जुड़ा रहा। 1992 में विवादास्पद घटनाओं के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। यह निर्णय उनके समर्थकों और आलोचकों- दोनों के लिए चर्चा का विषय बना, लेकिन इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो सत्ता से अधिक अपने सिद्धांतों को महत्व देता था।

मुख्यमंत्री पद के अलावा कल्याण सिंह ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनका व्यवहार सादा, स्पष्ट और आमजन के प्रति संवेदनशील रहा। कल्याण सिंह को हमेशा एक ओबीसी नेता के रूप में देखा गया, जिन्होंने पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी सरल जीवनशैली, स्पष्ट वक्तव्य और निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते थे। 21 अगस्त 2021 को उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति का एक सशक्त अध्याय समाप्त हो गया। कल्याण सिंह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सादगी, संघर्ष और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कोई भी व्यक्ति राजनीति में स्थायी पहचान बना सकता है।

प्रेमः सिर्फ उत्सव नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी भी

वेलेंटाइन वीक के बीच वास्तविकता से संवाद

आज का दौर तकनीक, गति और सूचनाओं का दौर है, लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक कड़वा सच यह भी है कि यह 'बाजारवाद' द्वारा संचालित सोच का युग है। बाजार आज केवल उत्पाद नहीं बेच रहा, वह हमारी संवेदनाएँ, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारे प्रेम करने के तरीकों को भी नियंत्रित करने लगा है। इन दिनों वेलेंटाइन वीक की बयार है रोज डे के गुलाबों से लेकर चॉकलेट डे और टेडी डे के उपहारों तक, हर दिन के साथ एक नया उत्पाद और एक नया मनोवैज्ञानिक दबाव युवा मस्तिष्क पर बनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि इस उत्सव की चकाचौंध के समानांतर एक डरावनी हकीकत भी है। प्रेम के नाम पर बिछाए जा रहे छलावे के कारण रोजाना युवाओं के भावनात्मक शोषण और ब्लैकमेलिंग की घटनाएँ सामने आ रही हैं। जो प्रेम जीवन का संबल होना चाहिए था, वही आज युवाओं को नशे और अपराध के दलदल में धकेल रहा है।

यही कारण है कि आज का युवा जागरूक होने की बजाय अक्सर आकर्षण और तात्कालिक सुख के कुहासे में भटकता नजर आता है। वर्तमान में हम 'वेलेंटाइन वीक' के मध्य में हैं, जहाँ हर दिन के साथ एक नया उत्पाद और एक नया मनोवैज्ञानिक दबाव युवा मस्तिष्क पर बनाया जा रहा है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि ये दिन मनाए जाने चाहिए या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या प्रेम जैसे महान और व्यापक शब्द को हम केवल उपहारों और बाजारीकरण की संकीर्ण मानसिकता तक सीमित कर देंगे? हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होगा और प्रेम को इन सीमाओं से बाहर निकालकर व्यवहारिक जीवन के धरातल पर लाना होगा। यह केवल एक व्यक्ति की क्षति नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि प्रेम हमें पतन की ओर ले जा रहा है, तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता।

आकर्षण का छलावाः इस बाजारवादी चकाचौंध के बीच सबसे बड़ा संकट उन युवाओं पर है जो अभी मानसिक रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। किशोरावस्था और शुरुआती युवावस्था में भावनाओं का उफान इतना तीव्र होता है कि प्रेम और क्षणिक आकर्षण के बीच का अंतर धुंधला पड़ जाता है। आज 'दिखावे' की संस्कृति ने युवाओं को एक ऐसी अंधी दौड़ में धकेल दिया है, जहाँ वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। जब प्रेम का आधार 'समझ' के बजाय 'दिखावा' बन जाता है, तभी भटकाव की शुरुआत होती है। युवा अक्सर यह तय नहीं कर पा रहे कि वे वास्तव में किसी के प्रति समर्पित हैं या केवल एक बाजारी 'ट्रेंड' का हिस्सा बनकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

आज का युवा जागरूक होने की बजाय अक्सर आकर्षण और तात्कालिक सुख के कुहासे में भटकता नजर आता है। वर्तमान में हम 'वेलेंटाइन वीक' के मध्य में हैं, जहाँ हर दिन के साथ एक नया उत्पाद और एक नया मनोवैज्ञानिक दबाव युवा मस्तिष्क पर बनाया जा रहा है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि ये दिन मनाए जाने चाहिए या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या प्रेम जैसे महान और व्यापक शब्द को हम केवल उपहारों और बाजारीकरण की संकीर्ण मानसिकता तक सीमित कर देंगे?

भटकाव के भयावह परिणामः वर्तमान परिस्थितियाँ गंभीर और चिंताजनक हैं। रोजाना समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जहाँ प्रेम के नाम पर युवाओं को जाल में फँसाया जा रहा है। मानसिक अपरिपक्वता के कारण कई युवा सोशल मीडिया और आभासी दुनिया के छलावे को सच मान बैठते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे ब्लैकमेलिंग, भावनात्मक शोषण और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रेम में असफलता या गलत संगत के प्रभाव में कई युवा नशे की लत की ओर भी धकेले जा रहे हैं। जिसे वे प्रेम का 'सहारा' समझते हैं, वही कई बार उनके भविष्य की बर्बादी का कारण बन जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की क्षति नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि प्रेम हमें अपराध, अवसाद या नशे की ओर ले जा रहा है, तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता।

बाजारवाद की वैचारिक दासताः बाजार का अपना तर्क है वह भावनाओं को अवसर में बदलता है। इसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब शुरू होती है जब हम प्रेम को उसकी 'कीमत' से आँकने लगते हैं। जब एक महँगा उपहार प्रेम की गहराई का पैमाना बन जाता है, तब संवेदनाओं का पतन शुरू होता है। युवाओं को आत्मचिंतन करना होगा कि क्या उनका प्रेम स्वतंत्र है, या वे केवल उस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसे विज्ञापन और सोशल मीडिया एल्गोरिदम दिशा दे रहे हैं। प्रेम को केवल एक विशेष दिन या सप्ताह तक सीमित कर देना उसकी गरिमा को छोटा करना है। वास्तविक प्रेम व्यवहार में निरंतरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की मांग करता है, न कि केवल विशेष अवसरों पर प्रदर्शन की।

प्रेम की वास्तविक सार्थकताः सच्चा प्रेम वह है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए, न कि वह जो आपको आपकी पढ़ाई, करियर या परिवार से विमुख कर दे। यदि कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचा रहा है या आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक मोह है। प्रेम केवल "आई लव यू" कह देने की औपचारिकता नहीं है; प्रेम का वास्तविक अर्थ है "मैं तुम्हारे प्रति और तुम्हारी गरिमा के प्रति उत्तरदायी हूँ।" इस पूरे परिदृश्य में समाज और परिवार की भूमिका केवल 'पहरेदार' की नहीं, बल्कि 'मार्गदर्शक' की होनी चाहिए। जब घर में संवाद की कमी होती है, तो बच्चा बाहर के आकर्षण और भ्रम में जल्दी फँसता है। हमें उन्हें डिजिटल सुरक्षा और भावनात्मक मजबूती के संस्कार देने होंगे।

उत्सव से संस्कार तकः प्रेम से भागना समाधान नहीं है और प्रेम के नाम पर भटक जाना भी नहीं। आवश्यकता है सोच के विस्तार, समझ की गहराई और भावनाओं की जिम्मेदारी की। प्रेम को उत्सव से आगे बढ़कर एक संस्कार और नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करना होगा। जब प्रेम संवेदना बन जाए, सम्मान बन जाए और जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बन जाए, तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। युवाओं को यही समझना है और समाज को यह साहस के साथ सिखाना है। प्रेम अंततः बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति और संबल का मार्ग होना चाहिए।

आम बजट 2026

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा। लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। जिसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा।इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनयाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग, प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। क्योंकि इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला के तेल, डेनमार्क के ग्रीनफील्ड और आर्कटिक के दुर्लभ खनिजों पर टिकी हैं।चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में खनिज उत्खनन में लग गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के हित हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र,खेलकूद सामग्री, जैविक दवाओं, कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स, के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है।

दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के

लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। हालांकि ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है।भारत ने अब खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि भारत की धरती पर इस नजरिए से प्रचुर मात्रा में धरती के गर्भ में हर तरह के खनिज मौजूद हैं। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। इस बजट से इस व्यापार को मजबूती मिलेगी।

ओडिशा, केरल, आंध्र, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश की धरती के गर्भ में खनिजों का खजाना भरा पड़ा है। इसके दोहन के लिए उद्योगपति बेरकरार हैं।लेकिन पर्यावरणीय अड़चनों के कारण पूंजीनिवेश से बचते हैं। लेकिन अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं।मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है।

इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं।सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे।एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

सवालों से डरती सत्ता या सवालों से मजबूत होता लोकतंत्र

(पेज 1 का शेष)

लोकतांत्रिक दृष्टि से यह चिंताजनक और अपमानजनक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों द्वारा चुनिंदा पत्रकारों से ही सवाल कराए जाने की प्रवृत्ति पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। जानकारों का कहना है कि निजी आयोजनों में सवालों का चयन आयोजक की मर्जी से होना भले ही स्वीकार्य हो, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सरकारी अधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस, मंत्री या सरकारी विभाग की हो, तब सवालों को सीमित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई निजी मंच नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का माध्यम होती है। यहां पूछे जाने वाले सवाल सरकार या प्रशासन की पारदर्शिता की कसौटी होते हैं। यदि कठिन या असहज सवालों से बचा जाए तो यह संदेश जाता है कि सत्ता संवाद नहीं, केवल प्रचार चाहती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब संवाद का मंच रहेंगी या केवल नियंत्रित संदेश देने का जरिया बनकर रह जाएंगी। अगर सत्ता सवालों को सीमित करेगी तो नुकसान सिर्फ पत्रकारों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का होगा। मीडिया और लोकतंत्र के इस रिश्ते में एक बात साफ है जो सरकार सवालों का सम्मान करती है, वही वास्तव में लोकतंत्र का सम्मान करती है। कानूनी जानकार मानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों को सीमित करना सीधे तौर पर कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ जरूर है। लोकतंत्र में सरकार की मजबूती सवालों से नहीं, उनके जवाब देने की क्षमता से तय होती है। सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की आज़ादी केवल पत्रकारों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा प्रश्न है। अगर सवाल सीमित होंगे, तो जवाबदेही भी सीमित हो जाएगी। लोकतंत्र में मजबूत वही सरकार मानी जाती है जो सवालों का सामना करती है, न कि उनसे बचती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी को मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त है।

जब सवाल ही नहीं पूछने देंगे तो ऐसी पत्रकार वार्ता का क्या मतलब?

मैंने मुख्यमंत्री की अनेकों पत्रकार वार्ता में भाग लिया है। लेकिन इन पत्रकार वार्ता में केवल कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही सवाल पूछने की इजाजत मिलती है। मुझे हर बार स्वाल पूछने से रोका जाता रहा है। क्योंकि मेरे सवाल सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि सरकार की नीति और नीयत पर होते हैं। सच्चाई पर होते हैं। शायद यह सवाल सरकार को पसंद नहीं आते होंगे। मेरा सवाल है कि जब सवाल पूछने की आजादी ही नहीं होती है तो ऐसी पत्रकार वार्ता करने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो एक प्रेस विज्ञप्ति बनवाये और सभी जगह भिजवा दे, जिसे छापना होगा छापेंगे नहीं तो रद्दी की टोकरी में डाल देंगे।

अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे पत्रकारवार्ता का मतलब

इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मीडिया से खुले और ईमानदार संवाद करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वाजपेयी न केवल कुशल वक्ता थे, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक भी थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा साफ देखा गया कि वे कठिन और असहज सवालों से नहीं भागते थे, सवाल पूछने वाले पत्रकार को अपमानित नहीं करते थे और आलोचनात्मक प्रश्नों को लोकतंत्र की ताकत मानते थे। वाजपेयी का एक प्रसिद्ध जवाब है जब उनसे पूछा गया कि "आप अब तक कुंवारे क्यों हैं?" उन्होंने जवाब दिया, "मैं कुंवारा नहीं हूँ, अविवाहित हूँ।" उनके लहजे की शालीनता और तर्कसंगत दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल जनता के बीच बल्कि मीडिया के बीच भी बेहद लोकप्रिय बनाया। इसी तरह, मनमोहन सिंह, पी. चिदंबरम, ज्योति बसु, शरद पवार, सुषमा स्वराज, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमणियम स्वामी अन्य नेताओं ने भी प्रेस के सवालों का स्वागत किया और लोकतंत्र की इस मजबूत रीढ़ को बनाए रखा।

मीडिया का सम्मान लोकतंत्र की मजबूती का संकेत

प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के प्रति जवाबदेही का मंच होती है। यहां सवालों का चयन नहीं, बल्कि खुला संवाद अपेक्षित होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाद की जगह प्रचार का माध्यम बन जाती है, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। मीडिया का काम सिर्फ संदेश आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की आज़ादी केवल पत्रकारों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा प्रश्न है। अगर सवाल सीमित होंगे, तो जवाबदेही भी सीमित हो जाएगी। लोकतंत्र में मजबूत वही सरकार मानी जाती है जो सवालों का सामना करती है, न कि उनसे बचती है। प्रेस की आज़ादी कोई सुविधा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और उसका सम्मान करना सत्ता की जिम्मेदारी है। सवाल पूछना अपराध नहीं है, संवैधानिक अधिकार है।

झीलों का संरक्षण, हमारा अस्तित्व

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

झीलें प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं। झीलें केवल एक जलाशय नहीं हैं, वे हमारी धरती का जीवन हैं, वे हमारी सांसें हैं। मानव जाति की सभ्यता ने झीलों के किनारों पर बसकर अपनी शुरुआत की थी। ये पानी के स्त्रोत हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, और हमारे पर्यावरण के अनिवार्य अंग रहे हैं। लेकिन आधुनिकता और विकास की दौड़ में हमने इन जीवनदायिनी झीलों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत में डल झील, चिल्का झील और मानसरोवर जैसी झीलें हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। लेकिन आज ये खतरे में हैं। आज, जब जल संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हमें यह समझना होगा कि झील बचेंगे तभी हम बचेंगे।

झीलों का महत्व समझना सभी के लिए आवश्यक है। झीलें सिर्फ़ पानी का स्त्रोत नहीं होतीं। वे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से होती हैं, जिसमें जैव विविधता की भरमार होती है। झीलें प्राकृतिक जल शोधन का काम करती हैं और भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होती हैं। यह जलवायु को संतुलित करती हैं, आसपास के क्षेत्रों में नमी बनाए रखती हैं, और तापमान को नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा, झीलें पर्यटन, मछली पालन, और सिंचाई जैसे कई आर्थिक गतिविधियों का आधार होती हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से झीलों का पतन हो रहा है।

विकास के नाम पर झीलों का अतिक्रमण, जल प्रदूषण, और अवैध निर्माण ने इनकी हालत खस्ता कर दी है। शहरीकरण के बढ़ते दबाव और कृषि योग्य भूमि की मांग ने झीलों के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। कई झीलें कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गई हैं, जहाँ उद्योगों और घरों का अपशिष्ट सीधे डाला जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने भी जल को विषाक्त बना दिया है। जल का संकट बढ़ता जा रहा है इसलिए झीलों का संरक्षण आवश्यक है। भारत जैसे देश में, जहाँ एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर निर्भर है, जल संकट जीवन-मरण का सवाल है। अगर हमें इस संकट से उबरना है, तो हमें अपनी झीलों को बचाना होगा। झीलों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए न केवल सरकार को, बल्कि आम जनता को भी आगे आना होगा। झीलों का पुनर्जीवन सामूहिक प्रयास से ही संभव है। झीलों के संरक्षण के लिए सख्त और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत झीलों के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाना, जल प्रदूषण पर नियंत्रण, और अवैध अतिक्रमण को हटाना शामिल है। सरकार को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने होंगे और लोगों को भी जागरूक करना होगा। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी जिसमे अतिक्रमण करने वालो के विरुद्ध कड़ी कानूनी कारवाई का प्रावधान हो। झीलों का संरक्षण एक सामूहिक प्रयास है। स्थानीय समुदायों को इस मुहिम में शामिल करना आवश्यक है। वे झीलों की दशा-दिशा को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुभवों और सुझावों का सम्मान करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण और झीलों के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण उनके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। झीलों में गिरने वाले अपशिष्ट पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। उद्योगों और नगर पालिकाओं को अपने अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र को सुधारना होगा ताकि कोई भी हानिकारक रसायन झीलों में न गिरे। झीलों के पुनर्जीवन के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएँ चलानी होंगी। इनमें झीलों की सफाई, जल प्रवाह का पुनर्स्थापन, और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना शामिल है।

मीडिया की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। वह समाज को जागरूक कर सकती है, उसे संगठित कर सकती है, और सरकार पर दबाव डाल सकती है। झीलों की दुर्दशा और उनके पुनर्जीवन के प्रयासों की कहानियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके अलावा, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर भी झीलों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। हमें जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, रसायनों का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए, और कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा, सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लेकर हम अपनी झीलों को बचाने में योगदान कर सकते हैं।

कुछ सफल झील संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हमें प्रेरणा दे सकते हैं। बेंगलुरु की कुक्करेबेल्लुर झील का पुनर्जीवन, जहां स्थानीय समुदाय और सरकार ने मिलकर एक सफल संरक्षण अभियान चलाया, या उदयपुर की पिछोला झील का संरक्षण, जहां नागरिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि सामूहिक प्रयासों से हम अपनी झीलों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। झीलों का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। "झील बचेंगे तभी हम बचेंगे" केवल एक नारा नहीं, यह एक सच्चाई है जिसे हमें जल्द से जल्द समझना होगा। झीलों को बचाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें संगठित प्रयास करने होंगे। सरकार, समाज, और प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकारी योजनाओं जैसे 'अमृत सरोवर' का समर्थन करें और सामुदायिक स्तर पर सफाई अभियान चलाएँ।

आस्था-संस्कृति-परंपरा का अनुपम संगम; छत्तीसगढ़ की सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक

(पेज 1 का शेष)

02 फरवरी 2026 त्रिवेणी संगम राजिम के पावन तट पर नवीन मेला मैदान राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अतिथियों एवं संत-महात्माओं ने भगवान राजीवलोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी राजिम के कुंभ मेला में आकर अत्यंत शांति महसूस होती है। धर्म, आस्था और संस्कृति के इस संगम राजिम कुंभ मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु-संतों, श्रद्धालुजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

राजिम कुंभ मेला जैसे अद्भुत आयोजनों से पर्यटकों को भी विशेष आनंद आता हैं। मेले में कलाकारों का संगम, श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था और संतों के आशीर्वाद से राजिम मेले ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमें अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को आरक्षित और उन्नत करने की आवश्यकता है।हमें इस प्रकार के कला, संस्कृति और धार्मिक आयोजनों के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ पर्यटन मानचित्र में और उभर कर सामने आ सके।

'छत्तीसगढ़ का प्रयाग' है राजिम कुंभः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राजिम, जिसे 'छत्तीसगढ़ का प्रयाग' कहा जाता है, सदियों से भक्तों और संतों का आस्था केंद्र रहा है। राज्य सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेले को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित किया है और इसका नाम "राजिम कुंभ कल्प" रखा है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प और शिवरीनारायण मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये आयोजन राज्य की समृद्ध परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजिम कुंभ कल्प 2026 की प्रमुख विशेषताएंः

1 फरवरी (माघ पूर्णिमा) से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक।

राजिम (गरियाबंद जिला), महानदी, पैरी और सोंढूर का पावन त्रिवेणी संगम।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संजोना और पर्यटन को बढ़ावा देना।

शाही स्नान, साधु-संतों का समागम, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन-कीर्तन और सरस मेला।

यह मेला छत्तीसगढ़ के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मील का पत्थर माना जा रहा है।

राजिम कुंभ मेले के नदी क्षेत्र में झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र

राजिम कुंभ कल्प मेला में भगवान श्री कुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के समीप भव्य झांकियों का निर्माण किया गया है, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन झांकियों को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंच रहे हैं। राम दरबार की झांकी में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान से जुड़े दृश्यों को अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इसके पश्चात चारधाम यात्रा की झांकी दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है। इसमें भारत के चारों दिशाओं में स्थित बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम् धामों को सुंदर एवं प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। देशवासियों के मन में चारधाम यात्रा करने की जो अभिलाषा रहती है, उसका सजीव दर्शन श्रद्धालुओं को राजिम के त्रिवेणी संगम में ही प्राप्त हो रहा है। यह झांकियां विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो किसी कारणवश चारधाम यात्रा नहीं कर पाते। इसके अलावा अन्य झांकी भी लगाई गई है जो मेले घूमने आए लोगों खासकर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसे देखने के लिए लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। रोशनी, कलात्मक सजावट और धार्मिक प्रतीकों से सजी ये झांकियां राजिम कुंभ कल्प मेला की भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा को और अधिक बढ़ा रही हैं। इसमें बालाजी दर्शन, शिवलोक, विष्णु लोक, मृत्यु लोक, जैसी करनी वैसी भरनी, यमुनोत्री, शिव जी के द्वारा सती को उठाकर ले जाना, जटाशंकरी, समुद्र मंथन शिव की बारात आदि को दर्शाया गया है, जिसे देखकर दर्शक आनंदित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

मोदी
संग बढ़त हे
छत्तीसगढ़

पीएम आवास योजना
26 लाख
से अधिक परिवारों को पक्की छत देने वाले

महतारी वंदन योजना
70 लाख
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले

पीएम किसान सम्मान निधि
26 लाख
किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाले

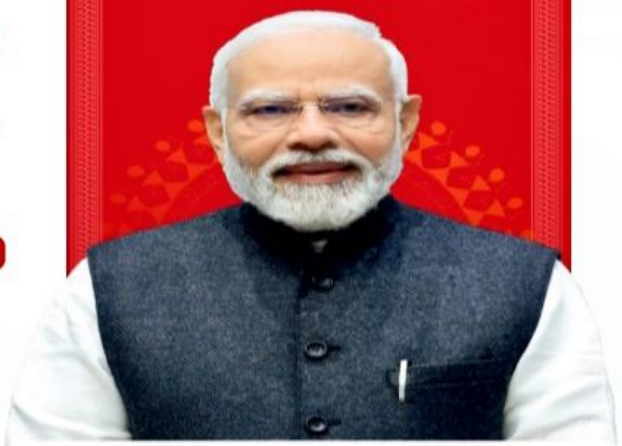

तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹5500 मानक बोरा
13 लाख
संग्राहक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले

उद्यम क्रांति योजना
युवाओं को स्वरोज़गार के लिये 50% सब्सिडी पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाले

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
5.62 लाख
भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने वाले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
37 लाख
महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाले

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना
37 हजार
से अधिक राम भक्तों को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराने वाले

छत्तीसगढ़
में शांति, विश्वास
और विकास का मार्ग
हो रहा प्रशस्त

R.O. No. : 13643/ 1

श्री विष्णु देव साय
मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)